हिन्दुस्तान, 22.10.1996

चकमा आदिवासियों का अनिश्चित भविष्य

— शशिधर खां

भारत और बंगलादेश के त्रिपुरा व चटगांव पहाड़ी क्षेत्र वाले सीमावर्ती इलाकों का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया है, लेकिन अभी तक दोनों देशों की सरकारों के रुख से लगता नहीं है कि किसी ने भी इस समस्या को गम्भीरता से लिया हो।

हुआ यों कि इस महीने के प्रथम सप्ताह में ढाका के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के रंगामाटी जिले में चकमा आदिवासियों के अधिकारों के लिए पिछले २० वर्षों से संघर्षरत शांतिवाहिनी छापामारों ने एक ही रात में जबर्दस्त हमले में ३० सुरक्षाकर्मियों की हत्या करके दिखा दिया कि बंगलादेश की सरकार भले ही उनकी ओर से आंखें मूंद ले पर वे अपना हक हासिल करने के लिए हमेशा सजग हैं। बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उस गांव के दौरे पर गयीं, सुरक्षाकर्मियों के परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि आदिवासियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालना चाहिए। ढाका लौटकर उन्होंने चकमा प्रतिनिधियों या शांतिवाहिनी के नेताओं को बातचीत के लिए बुलावा भेजने की जरूरत नहीं समझी, उल्टे पूरे चटगांव जिले में सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाकर उन्हें किसी भी परिस्थिति में कड़ाई से निपटने के निर्देश दे दिए गए। शेख हसीना ने यह भी कहा कि भारत में रह रहे चकमा शरणार्थियों की वापसी के लिए वह भारत सरकार से अधिकारी स्तर पर शीघ्र ही बातचीत शुरू करने वाली हैं। लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि चकमाओं के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी जबकि शांतिवाहिनी छापामारों ने इस हत्याकांड के दौरान ही एलान कर दिया था कि अगर चकमाओं के साथ सरकार का रवैया नहीं बदला तो चटगांव में एक भी सुरक्षा जवान जिंदा अपने घर नहीं लौट सकेगा। चकमा आदिवासियों के नेता अपने भाई-बंधुओं की बदनीयती के लिए बंगलादेश की सरकार को जिम्मेवार मानते हैं, जबकि बंगलादेश की अभी तक की सरकार चटगांव पहाड़ी क्षेत्र की अशांति के लिए भारत पर दोषारोपण करती रही है। मौजूदा स्थिति यह है कि चटगांव में शांतिवाहिनी और सुरक्षाकर्मियों के बीच टकराव दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो उसका खामियाजा निर्दोष चकमाओं को भुगतना पड़ेगा और वे बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे। शांतिवाहिनी तो हमला करके अथवा पुलिस द्वारा धावा बोले जाने का जवाब देकर भूमिगत हो जाते हैं और पुलिस उसके बाद छापामारों को खोजने के लिए लाचार ग्रामीणों को यातनाएं देती है तथा बेकसूरों को पकड़कर उनके साथ बदसलूकी करती है।

त्रिपुरा सरकार ने अपनी बंगलादेश से लगने वाली सीमा को कंटीले बाड़ से घेरकर अब चकमाओं के प्रवेश पर कड़ी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में १९७२ से रह रहे हजारों शरणार्थियों की वापसी संभव नहीं हो पा रही है, जिनमें सिर्फ दक्षिण त्रिपुरा में बने शरणार्थी शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों की संख्या ५६ हजार है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार ने काफी पहले स्पष्ट कर दिया था कि चकमा आदिवासियों के भरण-पोषण का खर्च उठाना उनके आर्थिक बूते के बाहर की बात है। वर्तमान मुख्यमंत्री दशरथ देव ने भी केन्द्र सरकार से और बंगलादेश सरकार दोनों से आग्रह किया है कि चकमाओं की स्वदेश वापसी की तत्काल व्यवस्था करें, क्योंकि उन्हें अपने राज्य की जनता का खर्च काटकर चकमा शरणार्थियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इन शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के नेता उपेन्द्र लाल चकमा और ब्रह्मनारायण चकमा का कहना है कि भारत सरकार बंगलादेश पर चटगांव में पुलिस व सेना का आतंकराज समाप्त करके, अनुकूल माहौल पैदा करने के लिए दबाव डाले ताकि चकमा लोग अपनी जमीन पर लौटकर शांति की जिंदगी गुजार सकें।

बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का पिछला कार्यकाल अभूतपूर्व संवैधानिक संकट के दौर से गुजरा, इसलिए उन्होंने चकमा समस्या की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। १९९३ में त्रिपुरा सरकार द्वारा हायतौबा मचाने के बाद बेगम जिया ने रुचि तो ली, लेकिन उससे चकमाओं का संकट हल होने के बजाय और बढ़ गया। पहले तो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और त्रिपुरा तथा चटगांव के सुरक्षा प्रमुखों के बीच बड़े ही नाटकीय ढंग से विचार-विमर्श का सिलसिला चला। आखिरकार बेगम खालिदा ने सीमित संख्या में चकमा आदिवासियों को वापस लेना स्वीकार किया, लेकिन यह व्यवस्था करने की जरूरत नहीं समझी कि चकमा लोग जब स्वदेश लौटेंगे तो रहेंगे कहां और खाएंगे क्या। क्योंकि, चकमाओं को अपनी जगह-जमीन से जबर्दस्ती बेदखल करके उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था और यह काम नियोजित ढंग से पुलिस व सेना के सहयोग से मुस्लिमों को बसाने के लिए किया गया।

इस साजिश को कामयाब करने में बेगम खालिदा से पहले बंगलादेश के शासक ले. जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद ने ही मुख्य भूमिका निभाई, जो फिलहाल भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल में हैं।

अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श का मुख्य विषय चकमाओं की स्वदेश वापसी पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना था, लेकिन बंगलादेश की सरकार को इनके लिए दर्द तो था नहीं, फिर चकमा के लिए उसे कुछ सोचने की जरूरत क्या थी। भारत सरकार ने त्रिपुरा से शरणार्थियों को सम्मान स्वदेश वापसी की व्यवस्था की और जब उन लोगों ने अपने देश की सीमा में कदम रखा तो पाया कि उनका गांव पराया हो चुका है। चटगांव और उसके आस-पास बस गये मुसलमानों ने न केवल उन्हें पहाड़ों, जंगलों व नदी किनारे खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर कर दिया बल्कि कइयों को दुत्कार कर भगा भी दिया। कुछ तो दुखी होकर भारत की सीमा में लौट आए और सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा कर्मियों की नाव किनारे लगने से पहले ही वे रो-रोकर कहने लगे कि उन्हें बीच नदी में डुबो दें, गोली मार दें, पर बंगलादेश न भेजें।

बहुतों ने मुस्लिम बहुसंख्यकों की मजदूरी करके और गाली-गलौच सुनकर ही सही, चटगांव में रहना मंजूर कर लिया।

उपेन्द्र लाल चकमा ने इस दोमुंही नीति की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और केन्द्र ने चकमाओं को जबर्दस्ती स्वदेश भेजे जाने पर रोक लगा दी। फिर त्रिपुरा सरकार द्वारा सीमा को सील कर दिए जाने के बाद से चकमा का आना भी बंद है। एक जगह समूह में कुटुम्ब की तरह रहने के आदी चकमा अधिकारियों का परिवार छिन्न-भिन्न होकर रह गया। कई परिवारों के आधे सदस्य बंगलादेश में हैं तो आधे भारत में। त्रिपुरा में रह रहे शरणार्थियों का भविष्य अधर में और चटगांव में जो रह रहे हैं वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें शेख हसीना से कुछ उम्मीद है।

स्वभाव से मेहनती और कट्टर बौद्ध मतावलंबी चकमा आदिवासियों को इस्लामी रीति-रिवाज अपनाने को मजबूर करने के लिए उनके साथ अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला वास्तव में बंगलादेश के प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान ने ही शुरू किया और १९७२ से चकमा लोग अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए भारत की शरण में आने लगे। बंगलादेशी पुलिस व सेना ने दर्जनों बौद्ध मठ तोड़ दिये, सैकड़ों मकानों में रातों में आग लगाकर चकमाओं को जिन्दा जला दिया और जो बाहर निकले उन्हें गोली मार दी गई तथा महिलाओं की अस्मत लूटी गई।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अब तक पांच हजार से ज्यादा चकमा मारे जा चुके हैं। फिर, १९७६ में उनमें एक विद्रोही गुट पैदा हो गया जिसने शांतिवाहिनी के नाम से जांबाजों का एक दस्ता बनाया और बंगलादेश की सेना व पुलिस से अपने अपमान का बदला लेना शुरू किया। इस अभियान को भी कई वर्ष हो गए, पर शांतिवाहिनी को आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। उग्र हमले और जवाबी हमले से खून-खराबा माहौल बना रहता है। →